2030 तक दालों में आत्मनिर्भर बनेगा भारत

नीति आयोग की रणनीति से 2047 तक उत्पादन होगा दोगुना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर. सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने भारत को 2030 तक दालों में आत्मनिर्भर (आत्मनिर्भर) बनाने और 2047 तक उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रणनीति की सिफारिश की है.

आत्मनिर्भर (आत्मनिर्भर) दाल उत्पादन पर अपनी रिपोर्ट में, आयोग ने कहा कि अगर सरकार इन रणनीतियों को अपनाती है, तो भारत का दाल उत्पादन 2030 तक 34.45 मिलियन टन (एमटी) और 2047 तक 51.57 एमटी तक पहुंच सकता है. यह 2022 के 26.06 एमटी के उत्पादन से काफी अधिक होगा.

प्रमुख सिफारिशें

रिपोर्ट में दाल उत्पादन बढ़ाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम सुझाए गए हैं. इनमें शामिल हैं-

लक्षित फसल-वार क्लस्टरिंग- विशिष्ट फसलों के लिए क्षेत्रों को बनाए रखना और विविधता लाना.

अनुकूलित प्रौद्योगिकियों को अपनाना- विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक उप-क्षेत्रों के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करना.

उच्च गुणवत्ता वाले बीज का वितरण- 111 उच्च-संभावित जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उपचार किट के वितरण पर जोर देना.

वन ब्लॉक वन सीड विलेज क्लस्टर- प्रत्येक ब्लॉक में एक बीज गांव क्लस्टर-आधारित खेती को बढ़ावा देना. इन सिफारिशों के अलावा, रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सक्रिय उपाय अपनाने और डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए व्यापक निगरानी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है.

आपूर्ति और मांग का विश्लेषण

रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर दालों की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर का भी विश्लेषण किया गया है. सकल उत्पादन, आयात, निर्यात, स्टॉक परिवर्तन और बीज, चारे तथा बर्बादी के लिए उपयोग जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने भविष्य के लिए अनुमान तैयार किए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले वर्षों में भारत में दालों का अधिशेष (सरप्लस) होने की उम्मीद है. 2030 तक 3.79 एमटी और 2047 तक 16.48 एमटी का अधिशेष होने का अनुमान है. इसका मतलब है कि भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा, बल्कि उसके पास निर्यात के लिए भी पर्याप्त दालें होंगी.

लेज चिप्स पैक पर किसानों की झलक

नयी दिल्ली, 05 सितंबर (वार्ता) स्वदेशी की अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी कंपनी पेप्सीको की भारतीय इकाई पेप्सिको इंडिया ने लेज चिप्स के पैक पर किसानों को जगह दी है. पेप्सीको इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि उसके आलू चिप्स ब्रांड लेज ने भारतीय किसानों को सम्मानित करने वाली अपनी पहल मिट्टी की चिट्ठी के तहत यह शुरुआत की है. लेज ने पहली बार लिमिटेड एडिशन पैक पेश किया है जिनमें भारतीय किसानों को दर्शाया गया है. इन पैकेट्स पर पुरुष और महिला किसानों के हाथ से बने चित्र हैं जिनके चारों ओर खेती के जीवंत दृश्य दिखाये गये हैं. साथ ही एक फिल्म भी तैयार की गयी है जिसमें आलू उगाने में किसान की मेहनत से लेकर चिप्स तैयार होने तक की कहानी दिखायी गयी है.

जीएसटी सुधारों से कपड़ा उद्योग को नई उड़ान

रेडीमेड कपड़ों पर 2,500 रुपये तक 5% जीएसटी

फाइबर और यार्न पर टैक्स घटाकर 5% किया गया

नई दिल्ली, 5 सितम्बर. केंद्र सरकार के नए जीएसटी सुधारों से भारतीय कपड़ा उद्योग में एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक देश को 350 अरब डॉलर की कपड़ा अर्थव्यवस्था बनाना है. कपड़ा मंत्रालय ने उद्योग के हितधारकों, निर्यातकों और कारीगरों के साथ मिलकर इन सुधारों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है.

लागत में कमी और रोजगार सृजन- यह सुधार लागत कम करने और संरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए किए गए हैं, जो संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेंगे. ये उपाय प्रधानमंत्री के %5एफ% (फाइबर टू फैशन टू फॉरेन) फॉर्मूले से प्रेरित हैं, जो भारत को एक वैश्विक वस्त्र शक्ति के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है.

कपड़ों पर जीएसटी को तर्कसंगत बनाने से उत्पादन लागत कम होगी, जिससे मांग बढ़ेगी और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर होगी. इन सुधारों में रेडीमेड कपड़ों और मेड-अप वस्तुओं पर 2,500 रुपये प्रति पीस तक 5% जीएसटी दर तय की गई है, जिससे किफायती परिधान विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं. इससे टियर 2 और 3 शहरों के साथ-साथ ग्रामीण बाजारों में भी मांग बढ़ने की उम्मीद है.

मंत्रालय के अनुसार, यह कदम परिधान उद्योग की श्रम-प्रधान प्रकृति को देखते हुए रोजगार के अवसरों को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करेगा, खासकर सिलाई और फिनिशिंग इकाइयों में महिलाओं के लिए.

हस्तशिल्प और कालीन को प्रोत्साहन

सरकार ने कालीनों और फर्श कवरिंग पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे भदोही और श्रीनगर जैसे केंद्रों से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, 36 हस्तशिल्प वस्तुओं, हथकरघा सूती गलीचों और हाथ से बुने हुए कालीनों पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. यह कदम कारीगरों के लिए राहत लेकर आएगा, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करेगा और भारत की समृद्ध शिल्प परंपराओं को बनाए रखेगा.

सेंसेक्स-निफ्टी में उतार-चढ़ाव

07 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स

6.7 अंक पर चढ़ा निफ्टी

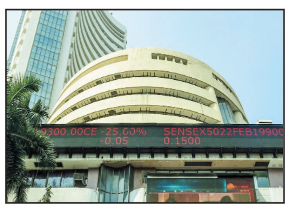

मुंबई, 05 सितंबर (वार्ता) घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को शुरुआती तेजी और उसके बाद बड़ी गिरावट से गुजरते हुये प्रमुख सूचकांक अंत में सपाट बंद हुये.बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 7.25 अंक टूटकर 80,710.76 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक 6.70 अंक की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति पर 24,741 अंक पर पहुंच गया.

एफएमसीजी, आईटी और रियलिटी सेक्टरों पर काफी दबाव रहा. वहीं, ऑटो, धातु और बैंकिंग सेक्टरों में तेजी रही.ऑटो कंपनियों में लिवाली से सेंसेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 2.34 प्रतिशत और मारुति सुजुकी का 1.70 फीसदी की बढ़त में रहा. पावर ग्रिड (1.21 प्रतिशत) और रिलायंस इंडस्ट्रीज (1.11 प्रतिशत) में भी एक फीसदी से अधिक की तेजी रही.एफएमसीजी और आईटी पर दबाव के कारण आईटीसी का शेयर 2.01 प्रतिशत टूट गया जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस में क्रमश: 1.55 फीसदी और 1.53 फीसदी की गिरावट रही.

एनएलसीआईएल नेवेली में शुरू करेगा हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट

नयी दिल्ली,05 सितंबर. एनएलसी इंडिया लिमिटेड तमिलनाडु के नेवेली में अपनी चार मेगावाट की हरित हाइड्रोजन प्रायोगिक परियोजना के लिए इलेक्ट्रोलाइजर की खरीद के उन्नत चरण में है.कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली ने कहा कि यह प्रायोगिक परियोजना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है जिसका उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है.उन्होंने शुक्रवार को नवीनतम रिपोर्ट में कहा,एनएलसीआईएल नेवेली में चार मेगावाट की हरित हाइड्रोजन प्रायोगिक परियोजना को आगे बढ़ा रही है.

कॉनकॉर संभालेगा भावनगर पोर्ट कंटेनर

कॉनकॉर-बीपीआईपीएल के बीच हुआ करार

कंटेनर टर्मिनल का संचालन और विपणन जिम्मेदारी

नई दिल्ली, 5 सितंबर. रेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली लॉजिस्टिक्स कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) ने गुजरात में विकसित हो रहे भावनगर बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल के संचालन, प्रबंधन और विपणन की जिम्मेदारी ली है. यह समझौता कॉनकॉर के लिए बंदरगाह परिचालन के क्षेत्र में एक नया कदम है.

कॉनकॉर ने इस समझौते के लिए भावनगर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीपीआईपीएल) के साथ करार किया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे देश में लॉजिस्टिक्स सुधार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रगति बताया है. कॉनकॉर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय स्वरूप के अनुसार, यह सहयोग दोनों कंपनियों के ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कॉनकॉर की स्थिति को और मजबूत करेगा.

बीपीआईपीएल ने पिछले साल गुजरात सागर परिषद के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत वह भावनगर बंदरगाह के विकास पर लगभग 4,500 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है. इस परियोजना के तहत, कंपनी 235 हेक्टेयर जमीन पर तीन बर्थ का कंटेनर टर्मिनल, दो बर्थ का बहु-उपयोगी टर्मिनल, एक रो-रो टर्मिनल और एक तरल वस्तुओं के लिए टर्मिनल बना रही है.

भारत का डीजल निर्यात यूरोप में उछला

रूस-ईयू तनाव के बीच भारत ने बढ़ाई सप्लाई, अमेरिका ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली, 5 सितंबर. यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोपीय यूनियन (ईयू) द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों और भारत की ओर से रूसी कच्चे तेल की खरीद ने एक नया भू-राजनीतिक समीकरण तैयार किया है. इस बीच, भारत ने यूरोप को डीजल का निर्यात रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है.

अगस्त 2025 में, भारत का यूरोप को डीजल निर्यात साल-दर-साल 137% बढ़कर 242,000 बैरल प्रतिदिन हो गया है. विभिन्न ऊर्जा कार्गो ट्रैकर्स के अनुसार, यह वृद्धि जुलाई की तुलना में 36% और पिछले 12 महीनों के औसत से 124% अधिक है.

निर्यात में वृद्धि के कारण

भारत से यूरोप को डीजल निर्यात में इस तेज उछाल के कई कारण हैं. इनमें से एक प्रमुख भारतीय रिफाइनरी द्वारा तय समय से पहले रखरखाव का काम पूरा करना शामिल है. इसके अलावा, यूरोप में सर्दियों की संभावित मांग को देखते हुए और जनवरी 2026 से ईयू द्वारा संभावित प्रतिबंधों से पहले स्टॉक बनाने की कोशिश भी एक बड़ा कारण है. ईयू का संभावित प्रतिबंध भारतीय रिफाइनरियों से होने वाली आपूर्ति को बाधित कर सकता है.

विदेशी मुद्रा भंडार 3.51 अरब डॉलर बढ़ा

झविदेशी मुद्रा का देश का भंडार 29 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

इससे पहले 22 अगस्त को समाप्त सप्ताह में यह 4.386 अरब डॉलर घटकर 690.72 अरब डॉलर रहा था. भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 29 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में 1.686 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गयी और यह 583.937 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

छोटे चाय उत्पादकों ने हरी पत्तियों पर एमएसपी मांगा

देश में 2.5 लाख छोटे चाय उत्पादक सक्रिय

कुल चाय उत्पादन में 50% से अधिक योगदान

कोलकाता, 5 सितंबर. देश के छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) ने सरकार से हरी चाय की पत्तियों के लिए न्यूनतम टिकाऊ मूल्य (एमएसपी) लागू करने की मांग की है. उनका कहना है कि ऐसा करने से उनकी आय और प्रतिस्पर्धा में स्थिरता आएगी.

भारत में लगभग 2.5 लाख छोटे चाय उत्पादक हैं, जो देश के कुल चाय उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान देते हैं.

छोटे चाय उत्पादकों ने सरकार से हरी चाय की पत्तियों के लिए 35 रुपये प्रति किलोग्राम का एमएसपी तय करने की अपील की है. उनका मानना है कि यह मूल्य उन्हें संकटपूर्ण बिक्री से बचाएगा. हाल ही में, छोटे चाय उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांग रखी.

मंत्रालय का सकारात्मक रुख

भारतीय लघु चाय उत्पादक संघों के परिसंघ (सीआईएसटीए) के अध्यक्ष बिजॉय गोपाल चक्रवर्ती ने बताया कि मंत्रालय ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है. मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर अध्ययन कराने और एक निष्पक्ष व पारदर्शी एमएसपी लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण समिति गठित करने का आश्वासन दिया है.इसके अलावा, सीआईएसटीए ने यह भी मांग की है कि छोटे चाय उत्पादकों को कृषि किसानों के समान माना जाए.

समाचार विशेष

भाजपा की उम्मीदवारी पर संशय के बादल

भागलपुर. भागलपुर सीट इस बार राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गई है. कई चेहरे अपनी किस्मत आजमाने को तैयार खड़े हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे खुद भले ही मैदान में नहीं हैं, लेकिन अपने बेटे अर्जित शाश्वत चौबे के लिए जोरदार लॉबिंग कर रहे हैं. इसी बीच यह चर्चा भी तेज हुई थी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी भागलपुर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं.

हालांकि, चौबे की मानें तो न तो शाहनवाज लड़ेंगे और न मैं. इस बयान से एक ओर शाहनवाज की संभावनाओं पर ब्रेक लग गया, तो दूसरी ओर अर्जित चौबे की दावेदारी और मजबूत हो गई. हालांकि, इस बीच सीट पर कई अन्य दावेदार भी लाइन में हैं, जैसे रोहित पांडेय (जो पिछले चुनाव में कांग्रेस से महज एक हजार वोट से हारे थे), मेयर वंसुधरा लाल, जिलाध्यक्ष संतोष साह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पवन मिश्रा, प्रीति शेखर, दिलीप मिश्रा और शिक्षाविद् प्रशांत विक्रम.

अब हालात यह हैं कि सीट पर समीकरण रोज बदल रहे हैं और बड़ा सवाल यही है, भागलपुर का असली दावेदार आखिर कौन बनेगा? हालांकि, सैयद शाहनवाज हुसैन अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन क्षेत्र में लगातार रहने की वजह से संभावित प्रत्याशियों के होश उड़े हुए हैं. भागलपुर विधानसभा सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है. विधायक अश्विनी चौबे के बक्सर से सांसद बन जाने के बाद 2014 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने नभय कुमार चौधरी को टिकट दिया था. कांग्रेस ने अजीत शर्मा को टिकट दिया. अजीत शर्मा ने जीत दर्ज की. 2015 के चुनाव में अजीत शर्मा के विरुद्ध अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत को टिकट दिया.

नेताओं की क्षेत्रों में चहलकदमी बढ़ी

संतोष कुमार पार्षद रह चुके हैं. वैश्य हैं और दो बार से जिलाध्यक्ष हैं. जिलाध्यक्ष होने की वजह से कद्दावर नेताओं के संपर्क में हैं. पवन मिश्रा खुद ब्राह्मण हैं और इनकी पत्नी गंगोता जाति से हैं. इनकी राजनीतिक पकड़ अच्छी है. पिछले कई चुनाव से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और टिकट के प्रवल दावेदार माने जा रहे हैं. प्रशांत विक्रम शिक्षाविद हैं. भाजपा में कई वर्षों से काम कर रहे हैं. इनकी भी राजनीतिक पकड़ अच्छी है और टिकट के लिए लगातार प्रयासरत हैं. प्रीति शेखर लंबे समय से राजनीति कर रही हैं. अच्छी वक्ता हैं और डिप्टी मेयर रह चुकी है. कई वर्षों से वार्ड पार्षद हैं.

संजय निषाद इतने आक्रामक क्यों?

5 फीसदी वोट बैंक की सियासत या भाजपा पर अतिरिक्त दबाव की रणनीति

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं. वे लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं.

अपनी अहमियत को बताने की कोशिश करते हैं. बार-बार भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन तोड़ लेने की बात करते हैं. हालांकि, पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद डॉ. निषाद के रुख में बदलाव दिखा था. उन्होंने मुख्यमंत्री को गार्जियन करार दिया. हालांकि, अब एक बार फिर पोस्टर वार के जरिए मामला गरमाता दिख रहा है. पोस्टर ब्रिजेंद्र कुमार त्रिपाठी की ओर से लगाया गया है, इसमें संदेश है- निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ.

कितनी ताकतवर निषाद पार्टी?- निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद) पार्टी यूपी की राजनीति में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करती दिखी. डॉ. संजय निषाद ने इस पार्टी के जरिए एक वोट बैंक को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से उन्हें बड़ा झटका लगा है. रामभुआल निषाद और लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जैसे नेताओं ने डॉ. संजय निषाद के इस वोट बैंक समग्र दावे को पूरी तरह से झटका दिया.

निषाद समाज को लेकर राजनीति

यूपी में निषाद समाज की वोट बैंक में हिस्सेदारी करीब पांच फीसदी है. निषाद समाज प्रदेश में मल्लाह, बिंद, मांझी, कहार, धीवर, निषाद, कश्यप के उपनाम से भी जाने जाते हैं. यूपी के कई इलाकों में यह समाज सियासी समीकरण उलट-पुलट करने की ताकत रखता है. गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, संतकबीर नगर, मिर्जापुर, भदोही, इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, फतेहपुर, हमीरपुर और सहारनपुर जिलों में निषाद वोटरों की बड़ी संख्या है. इसी ताकत के आधार पर निषाद पार्टी की कोशिश अधिक से अधिक ताकत बटोरने की है.

अजहरुद्दीन को एमएलसी बनाने की राजनीति

हैदराबाद. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन का पुनर्वास हो गया है. उनको तेलंगाना में विधान परिषद का सदस्य बनाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उनका नाम तय कराया है. गौरतलब है कि वे उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट से सांसद रहे हैं. लेकिन उसके बाद कई बार चुनाव लड़ने के बावजूद वे जीत नहीं पा रहे हैं. अलग अलग सीटों से उनको लड़ाया गया. उनको पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया लेकिन वे जीत नहीं पाए. पिछली बार कांग्रेस के पक्ष में हवा थी फिर भी वे जुबली हिल्स सीट से चुनाव हार गए थे. फिर भी कांग्रेस को उनकी उपयोगिता दिखती है और रेवंत रेड्डी के साथ उनके संबंध अच्छे हैं.

इस बीच जुबली हिल्स विधानसभा सीट से जीते बीआरएस के विधायक एम गोपीनाथ का निधन हो गया और जुबली हिल्स सीट खाली हो गई. अब वहां विधानसभा का चुनाव होने वाला है.

विशेष | **राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की बातें**

वसुंधरा-भागवत मुलाकात से बढ़ी हलचल

जोधपुर. भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जोधपुर दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और धार्मिक स्थलों के दर्शन भी किए. खास बात यह रही कि वसुंधरा राजे ने जोधपुर प्रवास के दौरान आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत से मुलाकात की और कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की. बुधवार सुबह भाजपा नेताओं ने अजीत भवन में पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की.

इनमें राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व जिलाध्यक्ष भोपाल सिंह बड़ला, राजसिको के पूर्व चेयरमैन मेघराज लोहिया और घनश्याम वैष्णव शामिल थे. सभी नेता वसुंधरा राजे के जोधपुर दौरे पर पहुंचे और उनसे चर्चा की. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सुबह लालसागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर पहुंचीं. यहां उन्होंने आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत से मुलाकात की. दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई. इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की बातें हो रही हैं.

सूत्रों के अनुसार, मुलाकात के दौरान कुछ अहम राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई. डॉ. भागवत इन दिनों अखिल भारतीय समन्वय बैठक के लिए जोधपुर प्रवास पर हैं. ऐसे में राजे की यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. भागवत से मुलाकात के बाद राजे सूरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा पहुंचीं. यहां उन्होंने रामस्नेही संत रामप्रसाद जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं और धार्मिक चर्चा की. इसके बाद वे राइका बाग स्थित जुगलजोड़ मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने सेनाचार्य अचलानंद गिरि महाराज से मुलाकात की, संतों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और अनुष्ठान में भी भाग लिया.

एसआई भर्ती अभ्यर्थियों से मुलाकात

अजीत भवन लौटने के बाद राजे ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुलाकात की. अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन भर्ती रद्द होने से उनके सामने भविष्य को लेकर संकट खड़ा हो गया है. इस पर राजे ने कहा कि दोषियों और नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना भी जरूरी है. राजे ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या को उचित मंच पर उठाया जाएगा.